सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

www.jalandharbreeze.com

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-8 • 14 AUGUST TO 20 AUGUST 2026 • VOLUME 04 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"छोटी कोशिशें कभी छोटी नहीं होतीं, वही बड़े बदलाव की शुरुआत बनती हैं।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	31°	26°
शनिवार	35°	26°
रविवार	31°	26°
सोमवार	33°	29°
मंगलवार	32°	24°
बुधवार	31°	25°
वीरवार	32°	25°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमला

बाएं हाथ में लगी चोट, निहंग के भेष में आए शख्स ने किया कृपाण से हमला

नांदेड़. महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। सुखबीर बादल अपने परिवार के साथ नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में माथा टेकने पहुंचे थे। इसी दौरान निहंग के भेष में आए एक शख्स ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के तौर पर हुई है। सुखबीर बादल के बाएं हाथ में चोट लगी और घटना के तत्काल बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं। वहीं, उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया।

बताया जा रहा है कि आरोपी ने कृपाण से सुखबीर सिंह बादल पर वार किया। हालांकि, घटना की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने हमले के बाद जसपाल सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। इससे पहले भी सुखबीर पर हमला हो चुका है। दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पूर्व डिप्टी सीएम पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। यह घटना उस वक्त हुई थी, जब बादल अकाल तख्त की सजा के बाद स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवा कर रहे थे।

'आप' नेता बलतेज पन्नू ने सुखबीर पर हमले की निंदा की

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने तख्त श्री हजूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, खासकर गुरुद्वारा साहिब में। घटना की निंदा करते हुए आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्था में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और गुरुद्वारों की पवित्रता और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। अकाली दल ने पंथ के नाम पर वोट मांगकर पांच बार सरकार बनाई, लेकिन उसकी सरकार के दौरान 2015 में कई जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा, 'जब लोग बेअदबी के खिलाफ शांति से विरोध करने निकले, तो उन पर पानी की बौछारें की गईं और गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें दो सिखों की जान चली गई।' उन्होंने कहा, 'उन घटनाओं का दर्द और गुस्सा आज भी सिखों के मन में है। इस भावना को समझने की जरूरत है।'

सुखबीर बादल से सीएम फडणवीस ने की मुलाकात, जांच का आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नांदेड़ के एक गुरुद्वारे में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के मकसद की जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से बात की और सुखबीर पर हुए हमले की जानकारी ली।

पीएम मोदी ने हरसिमरत को फोन कर जाना हालचाल

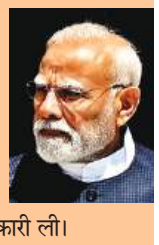

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की। मोदी ने सुखबीर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

सीमा पार से तस्करी मॉड्यूल से संबंधित पांच गिरफ्तार, 7 पिस्तौल व 2 किलो हेरोइन बरामद

डीजीपी गौरव यादव ने कहा- गिरफ्तार आरोपी अवैध हथियार प्राप्त करके आगे सप्लाई करते थे

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले दो बड़े नेटवर्कों का पर्दाफाश करके पांच व्यक्तियों को सात अवैध पिस्तौल और 2.030 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां निदेशक जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान परगट सिंह उर्फ पग्गा (30) और जनबर सिंह (20) दोनों निवासी गांव डल्ल, तरन तारन; बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला (30) निवासी गांव डोके, अमृतसर देहाती; अमनदीप सिंह उर्फ अमन (37) निवासी सरवरपुरा, अमृतसर और बलविंदर सिंह उर्फ काला (42) निवासी कोट आत्मा राम, अमृतसर के रूप में हुई है। बरामद की गई पिस्तौलों में चार .30 बोर (मेड इन चाइना) और तीन 9एमएम (मेड इन ऑस्ट्रिया) शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस टीमों ने आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आरोपियों की दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि शस्त्र अधिनियम के मामले में पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे जो अवैध हथियार प्राप्त करके उन्हें आगे अमृतसर एवं तरन तारन क्षेत्र मं सप्लाई करते थे। डीजीपी ने कहा कि आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने, विदेशी तस्करों से संबंधों की जांच-पड़ताल और व्यापक सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पहले मामले में पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी परगट उर्फ पग्गा, जनबर सिंह और बलविंदर उर्फ बिल्ला को पांच अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी परगट उर्फ पग्गा और बलविंदर उर्फ बिल्ला द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर पुलिस ने उनके द्वारा बताई गई जगह से दो और पिस्तौलें बरामद कीं। दूसरे ऑपरेशन के बारे में सी.पी. ने बताया कि विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अमनदीप उर्फ अमन और बलविंदर उर्फ काला को काबू किया और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2.03 किलो हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले थाना इस्लामाबाद, अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(8) के तहत एफ.आई.आर. संख्या 250 दिनांक 11.08.2026 और थाना सुल्तानविंड, अमृतसर में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21-सी और 29 के तहत एफआईआर संख्या 179 दिनांक 10.08.2026 दर्ज की गई हैं।

पीएसआईईसी प्लॉट अलॉटमेंट घोटाला : ईडी ने पंजाब के 4 शहरों में 11 ठिकानों पर छापेमारी

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने 4, 5 और 6 अगस्त 2026 को पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में 11 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ही पीएसआईईसी के कार्यालय में भी सर्वे किया गया। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। मामला पीएसआईईसी के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक प्लॉटों के अवैध आवंटन से जुड़ा है।

आरोप है कि प्लॉट अधिकारियों के रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य करीबी लोगों के नाम पर नियमों को दरकिनार कर आवंटित किए गए। सर्च के दौरान ईडी ने कई ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद कर जब्त किए हैं। ईडी ने यह जांच विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पीएसआईईसी के कई अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था।

ईडी की जांच में सामने आया कि कई औद्योगिक प्लॉट ऐसे लोगों को आवंटित किए गए, जिन्हें तकनीकी उद्योगों के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। निजी लोगों ने प्लॉट हासिल करने के लिए आवेदन पत्रों में फर्जी फर्मों और फर्जी पतों का इस्तेमाल किया। जांच के मुताबिक, पीएसआईईसी अधिकारियों से करीबी संबंधों के चलते इन लोगों को औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए गए। प्लॉट का कब्जा भी निर्धारित समय पर नहीं दिया जाता था और कई मामलों में इसमें वर्षों की देरी की गई। इसके बाद इस देरी की अवधि को 'जीरो पीरियड' मानते हुए आवंटन की तारीखों को कई साल आगे बढ़ाया जाता था। इस तरह बीच की अवधि के लिए बिना ब्याज के भुगतान योजनाओं का लाभ दिया जाता था। करोड़ों की संपत्ति और बैंक खातों पर कार्रवाई जांच में यह भी सामने आया कि कथित अवैध आवंटनों के बदले अधिकारियों को भारी रिश्वत दी गई। रिश्वत की रकम सीधे नकद लेनदेन और अलग-अलग वित्तीय माध्यमों से घुमाकर पहुंचाई गई।

शिवराज चौहान व प्रल्हाद जोशी आज पंजाब-हरियाणा दौरे पर

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय शिक्षा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी 14 अगस्त को पंजाब दौरे पर रहेंगे। यह दौरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी पारदर्शिता और खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 अगस्त को सुबह दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होकर चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में, सुबह 11 बजे पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी विशिष्ट अतिथि होंगे। वहीं, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभणिया भी उपस्थित रहेंगी।

चंडीगढ़ के कार्यक्रम के बाद मंत्रीगण दोपहर 2 बजे अजीजपुर गांव में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का उद्देश्य जमीन पर काम कर रहे किसानों से सीधे फीडबैक लेकर नीतियों को और व्यावहारिक एवं किसान-केंद्रित बनाना है।

दोनों सदनों से पारित हुए 12 विधेयक

संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

संसद का मानसून सत्र 2026 जो सोमवार यानी 20 जुलाई 2026 से शुरू हुआ था, आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान लोक सभा में 11 विधेयक और राज्य सभा में 2 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 12 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 12 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रपति द्वारा मानसून सत्र से पहले प्रख्यापित किए गए दो अध्यादेशों अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 और आय-कर (संशोधन) अध्यादेश 2026 को प्रतिस्थापित एवं इनके उपबंधों को समाविष्ट करने वाले दो विधेयकों पर दोनों सदनों में विचार और पारित किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर विचार किया गया और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को लोक सभा में 4 अगस्त को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया तथा 06 अगस्त को राज्य सभा ने उसे लौटा दिया। विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को जांच और रिपोर्ट हेतु सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। लोक परीक्षाओं से जुड़ी विद्यार्थियों की चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को लोक परीक्षा प्रणाली की ईमानदारी और विश्वसनीयता को मज़बूत करने की एक बड़ी पहल के रूप में पुर:स्थापित किया गया ताकि 2024 के मूल अधिनियम को संशोधित किया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित जांच और समय पर ट्रायल पक्का करना; राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार देना; दो महीने के अंदर जांच और तीन महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य करना; केंद्र सरकार को, जहाँ भी ज़रूरी हो, जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने में मदद करना; अपराधों के लिए सज़ा में बढ़ोतरी करना; और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक समयबद्ध अपीली तंत्र का उपबंध करना है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति ने इसे मंज़ूरी दे दी है।

एमएसएमई तंत्र को मजबूत करने के लिए सुधारों का अगला चरण

जालंधर ब्रीज. संसद के दोनों सदनों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का पारित होना, एमएसएमई के लिए भारत के कानूनी ढांचे को तेज़ी से बदलते तंत्र के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मूल अधिनियम के बाद से पिछले दो दशकों में, लाखों उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं और एमएसएमई राष्ट्रीय विकास, निर्यात और रोज़गार सृजन में अहम योगदान देने वाले बन गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य एमएसएमई इकोसिस्टम को ज़्यादा संवेदनशील और भरोसे पर आधारित बनाना है। इससे पंजीकरण आसान होगा, वर्गीकरण बेहतर होगा, ऋण तक पहुंच और समय पर भुगतान आसान होगा, विवादों का निपटारा डिजिटल और तेज़ होगा और नियमों का पालन आसान होगा।

इस संशोधन में उद्यमों के मुफ्त और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान किया गया है। इससे कई तरह की बाधाएं दूर होंगी और सरकार को बेहतर तरीके से लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अधिनियम के तहत पंजीकरण एक पात्रता है, जिसका दावा कोई भी कंपनी कर सकती है, यह कोई बाध्यता नहीं है।

यह संशोधन संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में निवेश और कारोबार के संयुक्त मानदंडों के आधार पर उद्यमों के वर्गीकरण के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस वर्गीकरण से फ्रेमवर्क को प्रौद्योगिकी, लागत, बाजार और व्यवसाय मॉडल में आने वाले बदलावों के अनुसार तेज़ी से ढाला सकता है और यह केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से इसकी सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार देता है।

जीतन राम मांझी
(लेखक केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं।)

ज़्यादातर एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी चिंता नियमित नकद प्रवाह की होती है, क्योंकि किसी छोटे उद्यम का एक भी भुगतान न मिलने का व्यापक असर कर्मचारियों के समय पर वेतन, कच्चे माल की खरीद और अगले ऑर्डर को स्वीकार करने पर पड़ता है, जिससे भुगतान में देरी होने से कंपनी के काम करने और आगे बढ़ने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस संशोधन में इस समस्या को तीन चरणों - रोकथाम, समाधान और कार्यान्वयन के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई है। रोकथाम: यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 'ट्रेड्स' (टीआरइडीएस) के माध्यम से एमएसएमई से संबंधित रसीद (इनवॉइस) के भुगतान और जानकारी देने को अनिवार्य बनाकर पारदर्शिता लाता है। राज्य सरकारें भी यही नियम अपने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते, 'ट्रेड्स' एक स्वीकृत इनवॉइस के आधार पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से तुरंत वित्तपोषण प्राप्त करने की सुविधा देता है। इससे आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान मिल जाता है, जबकि खरीदार तय तिथि पर बैंक या वित्तीय संस्थान को भुगतान चुकता करता है। इस प्रकार, रिसिवेबल्स (मिलने वाली रकम) आपूर्तिकर्ता के लिए लिक्विडिटी का ज़रिया बन जाता है, जिससे कंपनी को अपने कामकाज का प्रबंधन करने, बिलों का भुगतान करने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आसानी होती है।

समाधान: यह इस अधिनियम के विवाद-समाधान फ्रेमवर्क को और अधिक मजबूत करता है। यह राज्य सरकारों को मध्यस्थता और सुलह के लिए अतिरिक्त 'सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों' (एमएसइएफसी) की स्थापना करने में सक्षम बनाता है। यह मध्यस्थता और सुलह के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है तथा ऑनलाइन विवाद-समाधान को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इससे मामलों का तेजी से निपटारा होगा और एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिससे कंपनी प्रक्रिया और समय-सीमा की निश्चितता के साथ अपने जायज़ दावों को पेश कर सकेगी। कार्यान्वयन: 'सुविधा परिषदों' द्वारा दिए गए निर्णय के तहत मिलने वाली रकम को ज़मीन के लगान की बकाया राशि की तरह वसूला जा सकता है। यदि कोई खरीदार किसी फैसले को अदालत में चुनौती देना चाहता है, तो उसे तय राशि का 75 प्रतिशत अदालत में जमा कराना होगा और यदि वह चुनौती छह महीने तक लंबित रहती है, तो अदालत उस जमा राशि में से आधी राशि आपूर्तिकर्ता को जारी कर सकती है। इस प्रकार, लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण जायज दावों को खारिज नहीं किया जा सकेगा और अदालत में बीतने वाला समय अब केवल खरीदार के पक्ष में नहीं होगा।

यह संशोधन उद्यमों के लिए अनुपालन के प्रति अधिक संतुलित और विश्वास-आधारित दृष्टिकोण की दिशा में बदलाव को भी दर्शाता है। छोटे-मोटे उल्लंघन के लिए अब पहली बार में केवल चेतावनी दी जाएगी और अपराध दोहराए जाने पर अलग-अलग आर्थिक जुर्माने लगाए जा सकते हैं। नियमों के पालन की प्रक्रिया को ज़्यादा अनुमान लगाने लायक और आसान बनाकर, कंपनियाँ अब अपनी ऊर्जा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर लगा सकती हैं। इससे व्यवसाय करने में सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) और विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा मिलेगा। आखिर में, यह संशोधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में विश्वास का एक प्रतीक है, जो उन्हें नवाचार करने, रोज़गार पैदा करने, नए बाज़ारों में प्रवेश करने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाएगा। एक अधिक मजबूत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र 'विकसित भारत' के लक्ष्यों को

96 घंटे तक बिना किसी वीजा के फ्री में घूम सकते हैं सिंगापुर, जाने कैसे?

Travelling सिंगापुर की 96 घंटे की वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा (VFTF) उन यात्रियों के लिए है जो किसी तीसरे देश की यात्रा में सिंगापुर से होकर गुजरते हैं। इसके तहत बिना वीजा 4 दिन तक रुकने की अनुमति मिल सकती है। यह सुविधा भारतीय नागरिकों समेत कुछ अन्य देशों के यात्रियों के लिए है। हालांकि एंट्री का अंतिम फैसला इमिग्रेशन अधिकारी डॉक्युमेंट देखकर करते हैं।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

सिंगापुर की 96 घंटे की वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा (VFTF) उन यात्रियों के लिए है जो किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान सिंगापुर से होकर गुजरते हैं।

इस सुविधा के तहत कुछ लोग बिना वीजा के सिंगापुर में अधिकतम 4 दिन तक रुक सकते हैं। इसका फायदा भारत के नागरिकों, कुछ चीनी यात्रियों, CIS देशों, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान और जापान के नागरिकों को मिल सकता है। हालांकि यह एंट्री अपने आप नहीं मिलती। अंतिम फैसला सिंगापुर की इमिग्रेशन अथॉरिटी करती है, जो डॉक्युमेंट्स और यात्रा की शर्तें देखकर अनुमति देती है।

96 घंटे के अंदर निकलना जरूरी

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों को सिंगापुर में 96 घंटे तक बिना वीजा रुकने की अनुमति मिल सकती है, अगर सिंगापुर उनकी यात्रा में किसी तीसरे देश का ट्रांजिट पॉइंट हो। यात्री किसी भी साधन से आ सकते हैं, लेकिन 96 घंटे के अंदर हवाई या समुद्री रास्ते से निकलना जरूरी होता है।

एक महीना वैलिड होना चाहिए वीजा

भारतीय यात्रियों के पास अमेरिका, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या स्विट्जरलैंड का वैलिड वीजा या एंट्री परमिट होना जरूरी है। यह वीजा इस्तेमाल के लायक हो और सिंगापुर पहुंचने की तारीख से कम से कम एक महीना वैलिड होना चाहिए।

सिंगल-जर्नी वीजा के बारे में जान लें

अगर आपके पास सिंगल-जर्नी वीजा है, तो भी आप वापसी की यात्रा में सिंगापुर की 96 घंटे की वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा (VFTF) ले सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसी देश से लौट रहे हों जिसने वीजा दिया है, सिंगापुर से ट्रांजिट कर रहे हों और वीजा इस्तेमाल करने के बाद भारत सीधे न जा रहे हों।

किन पर वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा लागू होती है?

जो यात्री एयरपोर्ट के अंदर ही रहते हैं और इमिग्रेशन से नहीं गुजरते, उन्हें ट्रांजिट पैसेंजर माना जाता है और उन पर VFTF लागू नहीं होती। लेकिन जिन यात्रियों को सामान लेना, दोबारा चेक-इन करना या बोर्डिंग पास लेना होता है, उन्हें इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें सिंगापुर में प्रवेश माना जाता है और VFTF की सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

ट्रांजिट प्रक्रिया की जानकारी ले लें

कई लो-कॉस्ट एयरलाइंस ट्रांजिट के दौरान भी यात्रियों से इमिग्रेशन क्लीयर करवाती हैं। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से ट्रांजिट एयरपोर्ट की पूरी प्रक्रिया की जानकारी जरूर ले लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

सिंगापुर घूमने का मौका मिले

सिंगापुर जाने वाले सभी यात्रियों को स्वास्थ्य और इमिग्रेशन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। केवल एलिजिबल होना ही एंट्री की गारंटी नहीं है, क्योंकि आखिरी फैसला एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी लेते हैं। अगर आप योग्य हैं, तो भारतीय यात्रियों को 96 घंटे की वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा मिल सकती है, जिससे बिना अलग वीजा लिए लंबे लेओवर के दौरान सिंगापुर घूमने का मौका मिलता है।

LIFE MANTRA

इन 8 कामों को कर लिया तो बाद में बिल्कुल ना पछताएं, लेडीज ध्यान दें!

महिलाएं अक्सर खुद से पहले अपने पति, परिवार और बच्चों को रखती हैं और अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो केवल उनकी खुशी के लिए था तो बाद में वो बहुत पछताती हैं और मन में गिल्ट फील करती है। लेकिन लाइफ मंत्र कहता है कि इन...

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

महिलाएं अक्सर खुद के लिए कुछ करती हैं तो उनके मन में पछतावे वाली फीलिंग आने लगती है। कई बार वो खुद के लिए कुछ करते समय इतना ज्यादा परिवार, बच्चे, पति के बारे में सोचने लगती हैं कि उन्हें गिल्ट फील होने लगता है। लेकिन ये 8 चीजें आपके मन की खुशी के लिए जरूरी है और शायद इसे करने से घर का माहौल भी ज्यादा खुशनुमा होगा। क्योंकि जब आप खुद के लिए कुछ करेंगी तो आप खुश होंगी और घर वालों की बातें उतनी बुरी नहीं लगेंगी, जिससे घर में झगड़े भी कम होंगे। तो अगर आप इन 8 कामों को कर रहीं तो बाद में बिल्कुल ना पछताएं।

खुद के लिए टाइम निकालना

घर में पति, बच्चे, सास-ससुर हैं और आप पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहती हैं। इतने बिजी शेड्यूल से खुद के लिए आपने एक घंटा निकाल लिया और पार्लर गईं, वॉक पर गईं या फिर यूं ही घूमने चली गईं। तो मन में किसी भी तरह का गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए समय निकालकर अच्छा महसूस हो रहा है तो उसे पछतावे की आग में ना झोंके।

ना कहना है जरूरी

कुछ चीजों के लिए ना कहना जरूरी होता है और जरूरी नहीं कि जब आपने ना बोला हो तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए। आपका मन किसी काम को करने का नहीं हो रहा तो फौरन ना बोल दें। और अक्सर महिलाएं ये 'ना' बोलने के बाद पछताती हैं जो आपको हरगिज नहीं करना।

मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं

किसी दोस्त, रिश्तेदार, चाची-मामी का मैसेज आया तो जरूरी नहीं कि आप फौरन उसका रिप्लाई करें। अगर आप आराम कर रहीं तो फोन कॉल्स और मैसेज जिनसे आप बात नहीं करना चाहतीं तो इग्नोर करें और इस बात का पछतावा मन में ना लाएं।

खुद पर पैसे खर्च किए

भले ही आप कमाती ना हो लेकिन घर के कामों से बचाती तो हैं। तो खुद पर थोड़े से पैसे खर्च करके अपने मन में किसी तरह का पछतावा ना लाएं। कोई शॉपिंग अपने मन की कर ली तो उसको लेकर गिल्ट मन में ना लाएं।

मदद मांगना

आपसे काम नहीं हो पा रहा और आपने घर के दूसरे सदस्यों से मदद मांग ली। तो इस मदद मांगने के बाद भले ही वो आपको सुनाएं लेकिन मन में किसी तरह का पछतावा लाने की जरूरत नहीं है। मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। इस बात का गिल्ट मन में बिल्कुल ना लाएं।

आराम करें

हर रोज एक जैसा काम करती हैं। लेकिन एक दिन काम करने का मन नहीं तो आराम कर लें। आपने काम के समय आराम किया और काम में देर हो गई तो इस बात को लेकर मन में किसी तरह गिल्ट या पछतावा लाने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि हर काम हर दिन एक समय पर पूरे हों। कुछ समय आप आराम कर सकती हैं, इस बात को समझें और घर वालों को समझने दें।

सबको खुश करना जरूरी नहीं

घर में इतने सारे सदस्य हैं तो जरूरी नहीं कि वो सारे आपकी बातों से, काम से पूरी तरह से खुश हों। कुछ लोगों को आपकी बातें, काम और पर्सनैलिटी नापसंद हो सकती है। सबको खुश करने की कोशिश ना करें और सबको खुश नहीं कर पा रहीं इस बात का मलाल दिल में ना पालें।

पहले खुद की केयर करें

आप बीमार हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा फिर भी घरवालों के लिए खाना बनाना है। जरूरी नहीं है पहले आराम करें और खुद को सही करें। फिर दूसरों का ख्याल करें। अपने आप की केयर करना कोई गलती नहीं और इस बात का गिल्ट मन में बिल्कुल ना लाएं। कई बार घर-परिवार में ऐसे मौके आते हैं जब आपको खुद के लिए कुछ करने पर महसूस कराया जाता है कि आपने गलत किया है लेकिन ऐसे किसी भी गिल्ट को खुद पर हावी ना होने दें और खुद पर ध्यान देने और फोकस करने पर बिल्कुल भी पछतावा ना करें।

डिस्क्लेमर : इस लेख में किए गए दावे यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

संडे सुबह चाय के साथ बनाएं गर्मागर्म क्रिस्पी पोहे की कचौड़ियां

रविवार की सुबह घर में हर किसी को आलस आता है। देर से उठने के बाद सब चाय और कुछ गर्मागर्म खाने की डिमांड करते हैं। ऐसे में आप बनाएं ये क्रिस्पी पोहे से बनी कचौड़ियां, जो टेस्टी भी लगेंगी और पेट भी भरेंगी...

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

संडे की सुबह होते ही सब कुछ टेस्टी की डिमांड करने लगते हैं। बारिश का मौसम चल रहा तो फ्राईड, क्रिस्पी फूड की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में पूरे परिवार के लिए आप फटाफट मिनटों में ये टेस्टी पोहे की कचौड़ी बनाकर रेडी कर लें। थोड़ी सी मेहनत और बिना पहले से किसी तैयारी के इसे बनाकर रेडी किया जा सकता है। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये कचौड़ियां टेस्टी लगती हैं और आपके लिए चाय के साथ नाश्ता देने की ये बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए नोट कर लें कैसे बनेगी गर्मागर्म क्रिस्पी पोहे की कचौड़ियां।

पोहे की कचौड़ी बनाने की सामग्री

250 ग्राम पोहा, 5-6 उबले हुए आलू, एक चम्मच जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, बारीक कटी हरी धनिया, नींबू का रस, तलने के लिए तेल, जीरा, बेसन एक कप, एक चम्मच अजवाइन, मोयन, एक चुटकी हींग।

पोहे की कचौड़ी बनाने की रेसिपी

- सबसे पहले पोहा यानी चूरा को पानी में भिगोकर रख दें।

अब अंदर की फिलिंग तैयार कर लें। फिलिंग बनाने के लिए पांच से छह कचौड़ी बनाने की मात्रा के हिसाब से आलू को उबाल लें।

- इन आलूओं को हल्का सा ठंडा हो जाने दें या फिर गरम ही छीलकर फोड़ दें।
- अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें। तेल गर्म होते ही इसमे जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालें। साथ में उबले आलूओं को फोड़कर डाल दें।
- तेज गैस की फ्लेम पर इन आलूओं को भून लें।
- जब ये अच्छी तरहसे भुन जाएं तो इसमे भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालें। नमक स्वादानुसार डालकर सारी चीजों को मिक्स करें और भूनते रहें।
- जब सब भुन जाएं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और सबसे आखिरी में नींबू का रस और हींग चुटकी भर डालकर मिक्स कर लें।
- अब इस तैयार पेस्ट को ढंककर रख दें और कचौड़ी का आटा तैयार करें।
- कचौड़ी का आटा बनाने के लिए भीगे हुए चूरे यानी पोहे को किसी बड़ी परात में लें। इसमे एक कप बेसन, अजवाइन और लाल मिर्च कुटी हुई डालें। साथ में थोड़ा सा नमक और स्वाद के लिए मोयन डाल दें।
- बस अब इसे आटे की तरह गूंथ लें। ध्यान रहे कि पानी अलग से लेने की जरूरत नहीं है भीगे हुए पोहे में काफी सारा पानी होता है। और अगर जरूरत है तो हाथों में तेल लगाकर इसे गूंथ लेंगे।
- बस अब गोल, छोटी लोई बनाएं और इसमे तैयार आलू की स्टफिंग को भरकर अच्छी तरह से गोल कर लें।
- फिर हल्के हाथ से चपटा करें और गर्म तेल में डालकर तल लें।
- बस तैयार है गर्मागर्म क्रिस्पी कचौड़ियां। जिसे चाय के साथ खाएं और कचोड़ियों के साथ हरी-तीखी चटनी या फिर टोमैटो सॉस सर्व करें।

बस से स्कूल जाता है बच्चा तो जरूर सिखाएं ये स्कूल बस सेफ्टी रूल्स

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बच्चा बच्चे को बस से स्कूल भेजना काफी सारे पैरेंट्स को रिस्की लगता है। लेकिन स्कूल जब दूर हो तो कोई और ऑप्शन नहीं बचता। बच्चे को अगर बस ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है तो बच्चे को ये तरह के बस सेफ्टी रूल्स जरूर सिखा दें। जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना या अनहोनी से बच्चे को बचाया जा सके। वैसे ये पांचों बातें केवल बच्चे को ही नहीं बल्कि उनके माता-पिता को भी ध्यान में रखनी चाहिए। जानें वो कौन सी 5 बातें हैं जो बस सेफ्टी रूल्स हैं और बच्चों को जरूर सिखाई जानी चाहिए।

बस के ब्लाइंड स्पॉट से दूर रहें : बच्चे को सिखाएं कि बस से उतर रहे या चढ़ रहे तो कुछ बस के आसपास कुछ जगहों पर भूलकर भी ना खड़े हों, ये बस के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहां पर खड़े होने पर बच्चा क्या कई बार बड़े इंसान भी ड्राइवर को नजर नहीं आते। चूंकि बस की ऊंचाई ज्यादा होती है तो वो ठीक बस के नीचे यानी फ्रंट मिरर के ठीक नीचे कुछ दूरी तक नहीं दिखता। यहीं सेम हाल बस के अगल-बगल और पीछे भी होता है। बच्चे को सिखाएं कि जब भी बस से उतरना या चढ़ना हो तो बस के दरवाजे के पास खड़े हों और बस से उतरने के बाद दरवाजे की सीध में ही दूरी बनाकर खड़े हों।

चलती बस में ना चढ़ें ना उतरें : कई बार स्कूल के लिए देर होती रहती है तो बच्चे चलती बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, बच्चे को समझाएं की चलती बस से उतरने का चढ़ने की कोशिश ना करें।

गार्ड या ड्राइवर के सिग्नल के बिना रोड क्रॉस नहीं करना : बस से उतरते ही रोड क्रॉस करने की गलती ना करें। जब बस में मौजूद गार्ड या ड्राइवर सिग्नल दे तभी रोड क्रॉस करना चाहिए।

बैग और जूते की लैस को बांधकर रखें : स्कूल के लिए घर से निकलने से पहले ही जूते के फीतों को अच्छी तरह से बांध कर निकलें। इसी तरह से बैग के पट्टों को भी चेक कर लें। बस में चढ़ते समय या उतरते समय इनकी वजह से फंसकर गिरने का डर हो सकता है। इसलिए पहले से ही बैग के पट्टों और जूते के फीतों को बांधकर रखें।

जल्दीबाजी ना करें : बच्चों को सिखाएं कि बस में चढ़ते या उतरते समय किसी भी तरह की जल्दीबाजी ना दिखाएं। अगर गार्ड लाइन लगाकर बच्चों को बस में बैठा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन इस बीच धक्कामुक्की या फिर जल्दी में बस में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें। इससे जल्दीबाजी में गिरने का डर होता है और चोट लग सकती है।

छोटे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बच्चे को सिखाएंगे : तो आपका बच्चा अनहोनी से बच सकता है। स्कूल बस से जाना है तो बच्चे की सेफ्टी स्कूल के साथ ही आपकी भी होनी चाहिए।

पनीर या चना: प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए कौन सा फूड है बेस्ट?

Health वेजिटेरियन हैं और अंडा-मीट से दूरी बनाकररखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वेजिटेरियन की कुछ हाई प्रोटीन डाइट को जानना जरूरी है। आमतौर पर लोग पनीर और सफेद चने को लेकर दुविधा में रहते हैं। तो जानें पनीर...

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन के सोर्स तो कई सारे हैं। लेकिन इन सोर्स में प्रोटीन की मात्रा कम और कैलोरी की मात्रा ज्यादा रहती है। ऐसे में काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर शरीर के प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन से फूड्स को खाने में शामिल करें। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स पनीर को माना जाता है।

लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन में लोग सफेद चने को खाने की सलाह देते हैं। ऐसे में काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर पनीर या सफेद चना में से क्या खाएं जो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी कर सके और साथ ही जरूरी न्यूट्रिशन भी दे। तो चलिए जानें सफेद चने और पनीर में से कौन सा फूड प्रोटीन के लिए बेस्ट है।

पनीर और सफेद चने में कितना प्रोटीन होता है?

पनीर में प्रोटीन की माला सफेद चने की तुलना में ज्यादा होती है।

- 100 ग्राम पनीर में 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वहीं,
- 100 ग्राम सफेद चने में मात्र 9 ग्राम प्रोटीन ही होता है।
- पनीर और सफेद चने के न्यूट्रिशन की तुलना
- 100 ग्राम पनीर में न्यूट्रिशन
- प्रोटीन- 21 ग्राम
- कैलोरी- 265 ग्राम
- फैट- 20 ग्राम
- कार्ब्स- 1.2 ग्राम
- कैल्शियम
- हेल्दी फैट्स और साथ में विटामिन बी 12
- सफेद चने में न्यूट्रिशन
- प्रोटीन- 9 ग्राम
- कैलोरी- 164
- कार्ब्स- 27 ग्राम
- फाइबर- 8 ग्राम

इसके साथ ही आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा होती है।

पनीर और सफेद चने के न्यूट्रिशन देखने के साथ ही लोगों को अपनी जरूरत और शरीर की क्षमता के हिसाब से दोनों को चुनना चाहिए।

पनीर या सफेद चने में से क्या खाएं?

इस सवाल का जवाब थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि लोगों को अपने शरीर की जरूरत और क्षमता देखकर ही दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए।

किसे पनीर खाना चाहिए

जिन लोगों को मसल गेन करना है, हाई प्रोटीन खाना लेना है और कार्ब्स कम लेना है उनके लिए पनीर बेस्ट है।

सफेद चना किसके लिए अच्छा होगा

वहीं सफेद चना फाइबर रिच फूड है, जिससे फैट कम रहता है। साथ ही चना हार्ट हेल्थ और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आप मसल्स गेन नहीं कर रहें केवल प्रोटीन इनटेक पूरी करना है, उनके लिए पनीर से ज्यादा बेहतर सफेद चना है।

तो अगली बार जब प्रोटीन सोर्स लेने की सोच रहे हैं तो पनीर और सफेद चने में से एक को अपनी जरूरत के अनुसार चुनें।

***नोट :** इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अमल करने से पहले डाक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।*

पाठकों में फिर से रुचि जगाना : किताबों को फिर से बैठक कक्ष में जगह देना

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

'बच्चे की दुनिया को समृद्ध बनाने के कई छोटे-छोटे तरीके हैं। उनमें से सबसे अच्छा तरीका है, पढ़ने का आनंद।'

भारत में शिक्षा पर चर्चा लंबे समय से 'पहुँच' पर केंद्रित रही है - यानि स्कूलों तक, किताबों तक, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब हम भारतीय शिक्षा के एक नए चरण की दहलीज पर खड़े हैं, तो हमारे सामने एक और इतना ही जरूरी सवाल है:

क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो पढ़ती है?

यह ऐसा सवाल है - जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं - जिसने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय (आरईपी) या राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। इस प्लेटफ़ॉर्म की परिकल्पना केवल एक डिजिटल संग्रहालय के रूप में नहीं, बल्कि घर, स्कूल और समुदाय के स्तर पर भारत की पढ़ने की संस्कृति को समृद्ध करने के जीवंत प्रयास के रूप में की गयी थी।

आज, आरईपी में 23 भाषाओं में 7,000 से ज्यादा चयनित किताबें मौजूद हैं, जो सैकड़ों प्रकाशकों के साथ साझेदारी में विकसित की गई हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप हैं। लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी एक ऐसा संग्रह बनाना नहीं था, जो लगातार बढ़ता ही जाए। इसके पीछे एक सोच-समझकर अपनाया गया तरीका है: एक ऐसा संग्रह बनाए रखना, जो चयनित, प्रासंगिक और जीवंत हो - जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण किताबें जोड़ी जाती हैं और अप्रासंगिक किताबों को हटाया जाता है। पैमाना मायने रखता है, लेकिन प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लगातार जुड़ाव अधिक महत्वपूर्ण हैं।

अर्चना शर्मा अवस्थी
(भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अपर सचिव हैं।)

बाधाओं को दूर करना, आदतों का प्रतिस्थापन नहीं : भारत के कई बच्चों के लिए - खासकर ग्रामीण, अर्ध-शहरी और पिछड़े क्षेत्रों में - पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य किताबों तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। सबसे नज़दीकी किताब की दुकान कई किलोमीटर दूर हो सकती है। स्कूल के पुस्तकालय में या तो किताबें पुरानी होती हैं या स्कूल अवधि के बाद उपलब्ध नहीं होती हैं। इन बच्चों के पास कल्पना तो है, लेकिन पठन-सामग्री मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय इस कमी को पूरा करता है: एक बच्चा, चाहे वह कहीं भी रहता हो या उसके परिवार का आय स्तर कुछ भी हो, अब अपने घर में पहले से मौजूद उपकरण के जरिए हजारों किताबों के पुस्तकालय तक पहुँच सकता है। बच्चे कभी भी और कहीं भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में किताबों पढ़ने का भी अवसर देता है।

लेकिन यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि यह पहल असल में क्या नहीं है।

यह छोटे बच्चों को ज्यादा समय तक स्क्रीन के सामने बिठाने का प्रयास नहीं है। यह परिवारों के लिए एक आमंत्रण है कि वे अपने पास मौजूद उपकरणों का अधिक सार्थक उपयोग करें - उस समय को साझा और समृद्ध अनुभव में बदलें, जो अन्यथा निष्क्रिय होकर, अकेले बैठकर या हानिकारक स्क्रॉलिंग या चीजें देखने में बीत जाता है।

माता-पिता का छोटे बच्चे को ज़ोर से पढ़कर सुनाना।

बड़े भाई/बहन का कहानी सुनाना।

परिवार का साथ बैठकर पढ़ने के लिए समय निकालना।

ऐसे समय में जब स्क्रीन अक्सर लोगों को एक-दूसरे से दूर करके अपने में ही उलझाए रखती है, किताबें - जिन्हें इन्हीं उपकरणों के ज़रिए पढ़ा जा सकता है - लोगों को फिर से एक साथ लाने की ताकत रखती हैं।

युवराज मलिक
(नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के निदेशक हैं।)

पढ़ने को स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि पारिवारिक समय बनाना। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय का उद्देश्य प्लेटफॉर्म के आयामों से कहीं अधिक गहरा है: इसका मकसद पढ़ने की आदत को फिर से घर के बैठक कक्ष में लाना है।

पढ़ना सिर्फ एक शैक्षणिक गतिविधि नहीं है। यह एक सामाजिक और भावनात्मक गतिविधि भी है। जब परिवार के सदस्य या दोस्त साथ में पढ़ते हैं, तो वे बातचीत, सहानुभूति और सोचने-समझने के लिए जगह बनाते हैं - यह साथ मिलकर ध्यान देने का एक ऐसा गुण है, जो ऐप-सूचना और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में बंटी ज़िंदगी में अब कम ही देखने को मिलता है। इस बारे में हुए अध्ययन लगातार बताते हैं कि जिन बच्चों को पढ़कर सुनाया जाता है और जो अपने आस-पास बड़ों को पढ़ते हुए देखते हैं, उनमें न सिर्फ़ पढ़ने-लिखने की बेहतर समझ विकसित होती है, बल्कि उनकी अंदरूनी दुनिया भी ज़्यादा समृद्ध होती है।

आरईपी अंतरपीढ़ी सहयोग की संभावनाएं भी खोलता है। युवा पाठक अपने दादा-दादी या नाना-नानी को पढ़कर सुना सकते हैं। किशोर अपने बड़ों की पसंदीदा कहानियों को पढ़ सकते हैं। ऐसा करने पर, पढ़ना सिर्फ़ अकेले में किया जाने वाला या मजबूरी का काम नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है - इसे 'मेरा समय' के साथ-साथ 'हमारा समय' भी कहा जा सकता है।

ऐसा करने पर, पढ़ना सिर्फ़ अकेले में किया जाने वाला या मजबूरी का काम नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है - इसे 'मेरा समय' के साथ-साथ 'हमारा समय' भी कहा जा सकता है।

एक समाज के रूप में, हमें अपने आप से एक आसान, लेकिन गहन सवाल पूछना चाहिए: क्या हम स्क्रीन के निष्क्रिय उपयोग का एक हिस्सा वापस ले सकते हैं और उसे उपयोगी पढ़ाई में बदल सकते हैं? हमारा मानना है कि जवाब हाँ है - यदि हम किताबें उपलब्ध कराएं, उन्हें आकर्षक बनाएं और पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि अपनी पसंद का काम बनाएं।

एक जीवंत और विकसित होता पुस्तकालय : पारंपरिक पुस्तकालय अपने अलमारियों में स्थिर और भौतिक आयामों से बंधे होते हैं - इसके विपरीत राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय को गतिशील बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपके हाथ में किताबों का खजाना है। यह पाठकों को यह व्यक्त करने भी मौका देता है कि कौन सी अन्य किताबें जोड़ी जानी चाहिए। उपलब्ध किताबें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में भी हैं, जिसे युवा पीढ़ी को जानना चाहिए।

इसका बहुभाषी आधार भी उतना ही अहम है। एक बच्चा उस भाषा में सबसे बेहतर और स्वाभाविक रूप से पढ़ता है, जिसमें वह सोचता है। 23 भाषाओं में किताबें पेश करके - आगे और विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के साथ - आरईपी भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करता है, इसे केवल एक प्रबंधनीय चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक रचनात्मक ताकत के रूप में देखता है, जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए।

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला द्वारा बांग्लादेश रेलवे को निर्यात के लिए रेल डिब्बों का पहला रेक तैयार

• **जालंधर ब्रीज** . कपूरथला

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, 12 अगस्त 2026 को बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 एल एच बी ब्रॉड गेज रेल डिब्बों वाले पहले रेक के रोल-आउट के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रहा है।

इस रेक में 03 AC स्लीपर कार, 03 AC चेयर कार, 11 नॉन-AC चेयर कार तथा 02 पावर कार शामिल हैं। इन रेल डिब्बों में कई विशिष्ट डिजाइन विशेषताओं एवं संशोधनों को शामिल किया गया है, जिनमें से अनेक LHB प्रकार के डिब्बों में पहली बार विकसित किए गए हैं।

इन कोचों को बांग्लादेश रेलवे की परिचालन एवं यात्री आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है। इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई रिक्लाइनिंग चेयर, स्टेनलेस स्टील आर्मरेस्ट एवं स्टेनलेस स्टील फुटरेस्ट तथा सीटों को कई पोजीशन में रिक्लाइन करने की सुविधा प्रदान की गई है। कोचों में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें AC कोचों में पंखे, इंटीग्रेटेड CCTV सर्विलांस सिस्टम, पैसेंजर अलार्म सिस्टम, आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियाँ, बेबी केयर रूम तथा प्रार्थना कक्ष शामिल हैं। विशिष्ट परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोचों की रूफ स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है, ताकि पीक ट्रैफिक अवधि के दौरान छत पर यात्रियों के अतिरिक्त भार को सहन किया जा सके।

इन कोचों की एक प्रमुख तकनीकी विशेषता यूरोपीय मानक EN 15227 के अनुरूप Crashworthy Design Provisions का समावेश है। इसके लिए कार बॉडी शेल के व्यापक पुनःडिजाइन की आवश्यकता पड़ी, जिससे टक्कर की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन कोचों की विद्युत प्रणाली को भी विशेष रूप से 415 V ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि भारतीय रेल के कोचों में सामान्यतः 750 V प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

RCF और बांग्लादेश रेलवे के बीच सहयोग की शुरुआत 2015-16 में 120 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की सफल आपूर्ति के साथ हुई थी। इस सफल साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश रेलवे ने वर्ष 2024 में एक बार फिर RITES के माध्यम से RCF को सात विभिन्न प्रकार के 200 ब्रॉड गेज यात्री कोचों के निर्माण एवं आपूर्ति का प्रतिष्ठित ऑर्डर प्रदान किया।

एक न्यायाधिकरण, जो अपने आप में पूर्ण है

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

हमारे सार्वजनिक अधिनियमों में न्यायाधिकरणों के गठन से जुड़े कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी इतनी बार पुनर्समीक्षा हुई है। 1987 के एस. पी. संपत कुमार मामले से लेकर नवंबर 2025 में मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित निर्णय तक, न्यायालयों ने कानून निरस्त किये, निर्देश जारी किए और फिर उसी आधार पर स्वयं को नए कानूनों की समीक्षा करते हुए पाया। यह विषय इतने चक्र से गुजरा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि समस्या कितनी कठिन रही है। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 इसीलिए ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंततः वास्तविक समस्या की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि समाधान भी खोज लिया है।

एन. वेंकटरमण
(भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (उच्चतम न्यायालय)

दूसरे देशों और स्वयं के अनुभव से मिली सीख : यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों को भी इसका सामना करना पड़ा है और उनका निदान ध्यान देने योग्य है। ब्रिटेन में जब सर एंड्रयू लेगट ने 2001 में इस क्षेत्र की समीक्षा की, तो पाया कि सत्तर से अधिक न्यायाधिकरणों का प्रशासन उन्हीं विभागों द्वारा किया जा रहा था, जिनके निर्णयों की वे समीक्षा करते थे। उन्होंने इसे मूल दोष माना। उनका उपाय कार्यकाल में बदलाव या योग्यताओं को परिष्कृत करना नहीं था। उनका समाधान था कि न्यायाधिकरणों को उनके प्रायोजक विभागों से अलग कर उनका प्रशासन एकल सेवा के अधीन किया जाए। यही सुधार 2007 के अधिनियम का आधार बना। यह सुधार संरचनात्मक था। उसने निर्भरता के लक्षणों को नहीं, बल्कि निर्भरता की वजह का समाधान किया।

भारत ने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को प्रारंभिक चरण में ही अपनाया और, कुल मिलाकर, यह सफल रही। 1941 में स्थापित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आज भी विशेषज्ञतापूर्ण न्यायनिर्णयन के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इस प्रारूप को अनुच्छेद 323ए और 323बी तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 द्वारा आगे बढ़ाया गया और बाद में विभिन्न नियामक क्षेत्रों में उस उच्च स्तर पर इसका विस्तार हुआ, जिसे उच्च न्यायालय नहीं ले सकते थे। पर हमारी समस्या अलग तरह की थी। जैसा कि न्यायालय की 2020 की टिप्पणी में कहा गया कि स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब न्यायाधिकरणों को अपने कार्य करने के लिए कार्यपालिका के कंधों का सहारा न लेना पड़े। **पहले के प्रयासों से समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सका :** इस बारे में सुधार एक से अधिक बार किए गए हैं और हर बार सच्ची भावना के साथ किए गए हैं। इसके बाद होने वाली अधिकांश मुकदमेबाजी इस बात को लेकर रही कि कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए या चार या पांच वर्ष का, न्यूनतम आयु पचास वर्ष होना स्वीकार्य है या नहीं, और एक नाम या दो नामों की समिति की सिफारिश होनी चाहिए। सम्मानपूर्वक कहना होगा कि इनमें से कोई भी बात मूल समस्या तक नहीं पहुंचती। स्वतंत्र न्यायाधिकरण अंकगणित पर निर्भर नहीं करते। कार्यकाल, आयु और नामों की संख्या वे लक्षण हैं जिनके माध्यम से रोग का निदान किया गया है। वे स्वयं बीमारी नहीं हैं।

मूल बात : मूल बात यह है कि न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संस्था होनी चाहिए। उसका अपना प्रतिष्ठान होना चाहिए, अपने सदस्यों के चयन का उसका अपना साधन होना चाहिए, उन पर निगरानी रखने और उन्हें अनुशासित करने की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए तथा परिसर, कर्मचारियों और धन की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां ये सभी व्यवस्थाएं मौजूद हों, वहां स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं।

नया विधेयक उन सभी बिंदुओं पर न्यायालय को उत्तर देता है, जिन पर न्यायालय अपनी बात कह चुका है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयास है जो उन उत्तरों को स्वयं लागू करने योग्य बना दे। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना कानून द्वारा की जानी है। उसका अस्तित्व, गठन और कार्य किसी कार्यपालिका आदेश से नहीं, बल्कि अधिनियम से संचालित होंगे और उसे चयन, निगरानी, अनुशासन तथा न्यायाधिकरणों की आवश्यकताओं के आकलन का दायित्व है। उसके चारों ओर एक स्थायी पेशेवर सचिवालय स्थापित किया जाएगा।

सर्वोच्चता, समान दूरी और नियंत्रण जो व्यवस्था को प्रभावी बनाते हैं : विधेयक में उन प्रत्येक बिंदुओं पर न्यायिक सर्वोच्चता बनाए रखी गयी है, जहां उसका महत्व है। आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उसमें न्यायिक बहुमत का प्रावधान है। समितियों की अध्यक्षता न्यायिक रूप से की जाती है तथा निर्णायक मत न्यायिक अध्यक्ष के पास ही होता है। चयन, निगरानी, अनुशासन और कार्य-प्रदर्शन—सभी का नेतृत्व न्यायिक तौर पर किया जाता है। यह उस बात के अनुरूप है जो न्यायालय आर. गांधी मामले के बाद से कहता आया है कि कार्यपालिका, जो सबसे बड़ी वादी है, उन लोगों के चयन में प्रमुख भूमिका नहीं निभा सकती जो उसके मामलों का निर्णय करते हैं।

समावेशी, पारदर्शी सरकारी खरीद का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जेम

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

सरकारी खरीद के लिए सरकार का ई-मार्केटप्लेस (जेम) वैश्विक स्तर पर एक पारदर्शी, समावेशी और कुशल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो 1.37 लाख सरकारी खरीदारों को 25 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है।

जेम प्लेटफार्म की विशेषता है कि यह खरीद से जुड़ी सभी प्रमुख गतिविधियों को एक बड़े डिजिटल मार्केटप्लेस में एकीकृत करता है। यह वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों को सरकार के समावेशी विकास के साथ जोड़ता है, जिससे यह पीएम मोदी के विकासित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है। 2016 में पीएम द्वारा इस परिवर्तनकारी डिजिटल पहल की शुरुआत के एक दशक में, जेम ने भ्रष्टाचार को मिटाकर और स्टार्टअप, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और छोटे शहरों के व्यवसायों को बढ़ावा देकर, सरकारी खरीद में क्रांति ला दी है।

उपयोगकर्ता-अनुकूल यह प्लेटफ़ॉर्म वास्तव में एक रत्न है, जिसने विवादित आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की जगह ली है, जिसकी प्रणालियाँ अस्पष्ट और गैर-प्रतिस्पर्धी थीं। इससे खरीदारी प्रणाली के केवल कुछ सुविधा-प्राप्त लोगों को ही अनुचित फ़ायदा मिलता था। यह उचित है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया, आधुनिक कार्यालय, वाणिज्य भवन, उसी ज़मीन पर बना है, जहाँ कभी वह पुरानी और संदिग्ध प्रतिष्ठा वाली संस्था हुआ करती थी। वाणिज्य और उद्योग के मंत्री के रूप में, मुझे गर्व है कि जेम, जिसे 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, अपनी शानदार सेवा के दस साल पूरे कर रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों का जश्न मनाने वाला पड़ाव नहीं है; बल्कि यह इस बात में एक बुनियादी और सफल बदलाव है कि कैसे सरकारी खरीद देश के निर्माण में योगदान देती है।

पीयूष गोयल
(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

पारदर्शिता, व्यवसाय करने में आसानी : उत्पाद खोजने और बोली लगाने से लेकर अनुबंध देने और भुगतान करने तक, पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर जेम ने मनमाने फैसलों को खत्म किया है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है और लोगों के भरोसे को मजबूत किया है। हर लेन-देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है जिसकी जांच की जा सकती है; इससे जवाबदेही बढ़ती है और सरकारी खरीद के प्रति निष्ठा मजबूत होती है।

जेम पीएम मोदी के व्यवसाय करने में आसानी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकल डिजिटल विंडो, आसान पंजीकरण, मानकीकृत प्रक्रिया और नियमित नीतिगत सुधार - जैसे अमानत राशि को ख़त्म करना और लेन-देन शुल्क को युक्तिसंगत बनाना - के जरिये जेम ने भागीदार बनने की बाधाओं को काफी हद तक कम किया है, जिससे सरकारी खरीद तक पहुंच आसान हो गयी है।

आत्मनिर्भर भारत : जेम ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाया है। घरेलू निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देकर, इसने स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया है और देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया है।

पोर्टल पर दिया गया हर ऑर्डर भारत की निर्माण क्षमता और आर्थिक संप्रभुता में एक निवेश है। खास बात यह है कि जेम में मात्रा के आधार पर लगभग 60% ऑर्डर और सकल माल मूल्य (जीएमवी) में 45% से ज़्यादा की हिस्सेदारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की है।

आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक : सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और विकसित भारत की मजबूत नींव

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जांच केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह सरकार की ऐसी नीतियों को दर्शाता है, जिनका केंद्र आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम किया है। इन लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है कि देश में लोगों द्वारा अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कमी आई है। यह खर्च पहले 65 प्रतिशत तक था, जो अब घटकर 43 प्रतिशत रह गया है।

जिला अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशु से लेकर बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर मरीज तक, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसेमंद, अच्छी गुणवत्ता वाले और किफायती चिकित्सा उपकरण बेहद जरूरी हो गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने, गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने, बीमारियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर निवेश किया जा रहा है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब जोर एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने पर है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और सस्ता, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय मजबूत बनाना है।

पहले ,भारत कई आधुनिक और जटिल चिकित्सा उपकरणों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर था। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे इलाज की लागत बढ़ी, आपूर्ति व्यवस्था पर बाहरी निर्भरता बनी रही और इन उपकरणों की पहुंच सीमित रही। इसी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 में देश के भीतर आधुनिक चिकित्सा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाना और जांच की लागत कम करना है। सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के पूरे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा उपकरण पार्क और दवा एवं चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना शामिल हैं।

जगत प्रकाश नड्डा
(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं।)

इन पहलों से देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, नए शोध, निवेश और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है। नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 50 से अधिक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का देश में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि भारत धीरे-धीरे दुनिया के चिकित्सा तकनीक क्षेत्र में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर रहा है।

सिर्फ चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केंद्र बनने के अलावा, भारत तेजी से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना भी रहा है, ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आधुनिक जांच सुविधाओं, शरीर की अंदरूनी तस्वीर लेने वाली मशीनों, शरीर में लगाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों, गहन चिकित्सा की मशीनों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराने से मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही इलाज की गुणवत्ता और समय पर इलाज मिलने में भी सुधार होता है। देश में ही चिकित्सा उपकरण बनने से विदेशों से आयात पर निर्भरता घटती है, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होती है और लागत कम करने के अवसर बढ़ते हैं।

भारत का विश्व स्तर पर पहचान बना चुका दवा उद्योग, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता, तेजी से फैलता डिजिटल ढांचा, तेजी से बढ़ता नए उद्यमों का क्षेत्र और कुशल मानव संसाधन अगली पीढ़ी की चिकित्सा तकनीक विकसित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर (एसएमडी) , इंटरनेट से जुड़े चिकित्सा उपकरण, रोबोट आधारित तकनीक और दूर से जांच जैसी नई तकनीकों में भारत के पास देश और दुनिया की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए नए समाधान विकसित करने के बड़े अवसर हैं। जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां दुनिया के बाजार में विस्तार कर रही हैं, गुणवत्ता भी भारत में बने चिकित्सा उपकरणों की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। सरकार नियामक व्यवस्था को मजबूत करने, मान्यता प्राप्त जांच सुविधाओं का विस्तार करने, चिकित्सा उपकरणों की प्रभावशीलता से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है। इससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी मजबूत होगी।

दुनिया के स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा देने वालों, नए उद्यमों और निवेशकों के बीच करीबी सहयोग जरूरी है। जब प्रयोगशालाओं में तैयार विचार आसानी से कारखानों तक और वहां से मरीजों तक पहुंचते हैं, तभी नए आविष्कारों को वास्तविक लाभ में बदला जा सकता है। सरकार ऐसी स्थिर और पारदर्शी नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनसे शोध, निवेश, तकनीकी साझेदारी और कारोबार करना आसान हो।

भारत जैसे-जैसे विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास एक-दूसरे को और मजबूत करेंगे। एक मजबूत चिकित्सा उपकरण उद्योग उच्च मूल्य वाले उत्पादन, कुशल रोजगार, निर्यात और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सस्ती, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय अधिक मजबूत बनेंगी।

15 अगस्त को लेकर जालंधर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, पूरी मुस्तैदी और आपसी तालमेल के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश

एडीजीपी नॉर्थ विजिलेंस ब्यूरो और पुलिस कमिश्नर ने स्टेडियम का लिया जायजा

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र जालंधर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजीपी एवं चीफ डायरेक्टर, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो नागेश्वर राव, आईपीएस और पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह, आईपीएस ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों, पीपीएस और डीसीपी हेडक्वार्टर परमिंदर सिंह, पीपीएस समेत गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम जालंधर पहुंचकर 15 अगस्त के मुख्य समारोह को लेकर चल रही तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों का मौके पर जायजा लिया। इस दौरान परेड, विभिन्न कार्यक्रमों, दर्शकों की आवाजाही, पार्किंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था समेत पूरे सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की गई।

एडीजीपी चीफ डायरेक्टर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और पुलिस कमिश्नर जालंधर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त के कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता, मुस्तैदी और आपसी तालमेल सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद 15 अगस्त के मद्देनज़र जालंधर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नागेश्वर राव, आईपीएस की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह, आईपीएस भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों, पीपीएस, डीसीपी हेडक्वार्टर परमिंदर सिंह, पीपीएस, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अन्य गजटेड अधिकारियों और सभी संबंधित थाना प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक में 15 अगस्त के मुख्य समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वीआईपी मूवमेंट, पार्किंग व्यवस्था, रूट सिक्योरिटी, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा समेत विभिन्न सुरक्षा पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। नागेश्वर राव ने अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र पूरी सतर्कता, मुस्तैदी और आपसी तालमेल के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

वहीं, पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह, आईपीएस ने भी पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शॉपिंग मॉल, संवेदनशील स्थानों, सरकारी इमारतों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, मुख्य मार्गों और महत्वपूर्ण स्थानों के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता की जांच की। इस दौरान संबंधित स्थानों पर पुलिस की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की गई और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

15 अगस्त से पहले जालंधर में पुलिस का फ्लैग मार्च

जालंधर (जालंधर ब्रीज). स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की ओर से गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह, आईपीएस के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों, पीपीएस, डीसीपी मुख्यालय परमिंदर सिंह, पीपीएस सहित पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। फ्लैग मार्च के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों, मुख्य सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र शहर में कड़ी चौकसी बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच बढ़ाने तथा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनज़र जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। शहर में लगातार गश्त, नाकाबंदी और वाहनों की जांच की जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस टीमें पूरी तरह सतर्क हैं।

उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने कहा कि "सुरक्षित जालंधर - शांतिपूर्ण स्वतंत्रता दिवस" के उद्देश्य से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है तथा शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी और सतर्कता बरत रही है।

'सड़क सुरक्षा फोर्स' एआई, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से पंजाब को भारत का रोड सेफ्टी हब बनाएगी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब पुलिस न केवल अपराधियों से राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि अपनी प्रमुख पहल 'सड़क सुरक्षा फोर्स' (एसएसएफ) के माध्यम से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी नए मानदंड स्थापित कर रही है। यात्रियों की जान बचाने के लिए समर्पित यह हाईवे पेट्रोल फोर्स ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और एआई-आधारित प्रेडिक्टिव प्रणालियों को एकीकृत करके पंजाब पुलिस को भारत की पहली 3डी पुलिस फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। समर्पित हाईवे पेट्रोल फोर्स का सकारात्मक प्रभाव उन सड़कों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिन पर यह फोर्स तैनात रहती है। फरवरी 2024 से जनवरी 2026 तक एसएसएफ ने 43,983 सड़क हादसों में पहुंचकर कुल 47,386 लोगों को सहायता प्रदान की। इन कार्रवाइयों के दौरान 19,973 लोगों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि 27,413 घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस प्रकार इस फोर्स ने तत्काल आपातकालीन सहायता और चिकित्सा मदद के माध्यम से लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हाईवे सुरक्षा के लिए समर्पित फोर्स के रूप में स्थापित पंजाब एसएसएफ का विशेष ध्यान निर्धारित हाईवे और प्रमुख सड़कों पर गश्त करने पर केंद्रित है। पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के विपरीत, एसएसएफ के जवानों को नियमित कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाता। उनकी मुख्य जिम्मेदारी सड़क सुरक्षा, तत्काल कार्रवाई और हादसा पीड़ितों की सहायता करना है। इस फोर्स के पास 144 हाईटेक वाहन और 1,600 से अधिक विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जिनमें लगभग 28 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हैं। एसएसएफ टीमों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के 4,100 किलोमीटर क्षेत्र में हर 30 किलोमीटर पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। एसएसएफ की टीमें हादसों पर औसतन 6 से 10 मिनट में कार्रवाई करती हैं, जो वैश्विक मानकों की तुलना में काफी तेज है।

डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने परेड का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उनके साथ डी.सी.पी. परमिंदर सिंह हीर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर भी मौजूद थे। परेड के निरीक्षण के बाद डिप्टी कमिश्नर ने परेड कमांडर आतिश भाटिया के नेतृत्व में निकाले गए शानदार मार्च पास्ट से सलामी ली। मार्च पास्ट में इंडो-तिब्बतीयन बॉर्डर पुलिस, पंजाब पुलिस (पुरुष), पंजाब पुलिस महिला विंग, पी.आर.टी.सी. जहान खेलां, पंजाब होम गार्ड्स, एन.सी.सी. लड़के, एन.सी.सी. लड़कियां, लायलपुर खालसा स्कूल लड़के, डी.एस.एस.डी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोढल रोड के स्काउट, लायलपुर खालसा स्कूल गर्ल्स तथा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू गार्डन की गर्ल गाइड्स और सी.आर.पी.एफ. का बैंड शामिल था।

इसके बाद विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मास पी.टी. शो और देशभक्ति के रंग में रंगी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 15 अगस्त को जिला स्तरीय समारोह के दौरान पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं संबंधी आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समारोह को निर्विघ्न और सुचारू ढंग से संपन्न कराने में कोई कमी बाकी न छोड़ी जाए।

उन्होंने अधिकारियों को सौंपी गई ड्यूटी पूरी तनदेही और समर्पण भाव से निभाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि समारोह के दौरान लोगों और विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों की आमद को ध्यान में रखते हुए उचित एंट्री, बैठने, सफाई, पीने के पानी आदि की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, सुचारू आवाजाही और पार्किंग के लिए उपयुक्त प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।

डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जिला स्तरीय समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाली हस्तियों और विभिन्न विभागों के शानदार कार्यप्रदर्शन वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति की भावना और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने जालंधर वासियों को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया।

इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) दिव्या पी., एस.डी.एम. जालंधर-1 शुभी आंगरा, एस.डी.एम. जालंधर-2 शायरी मल्होत्रा, ए.डी.सी.पी. सुखविंदर सिंह, सहायक कमिश्नर (ज) वरुण कुमार के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

आयकर विभाग, मुंबई ने खेल कोटे के तहत पंजाब के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियुक्त किया

• **जालंधर ब्रीज.** मुंबई/चंडीगढ़

आयकर विभाग, मुंबई ने खेल कोटे के तहत पंजाब के दो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्त किया है। नवनियुक्त खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र 12 अगस्त 2026 को मुंबई स्थित आयकर भवन में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई, श्री आलोक कुमार द्वारा प्रदान किए गए।

आयकर विभाग द्वारा 7 जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से 97 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों से कुल 3,595 आवेदन प्राप्त हुए। निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदनों की गहन जांच एवं मूल्यांकन के बाद 97 उम्मीदवारों का मेरिट के आधार पर चयन किया गया। भर्ती की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि चयनित खिलाड़ियों में 80 प्रतिशत से अधिक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जो विभाग में शामिल होने वाली खेल प्रतिभाओं के उच्च स्तर को दर्शाता है।

अनमोलप्रीत कौर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जश्नूर ढींडसा ने एशियाई पुरुष अंडर-20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया।

संत सीचेवाल ने भाई घनैया को 'भारत रत्न' देने की मांग उठाई

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने राज्यसभा में मानवता की निःस्वार्थ सेवा के महान प्रतीक भाई घनैया जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की पुरजोर मांग उठाई। उन्होंने भाई घनैया जी का जन्मदिवस 20 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की मांग भी की, ताकि देश की युवा पीढ़ी उनके सेवा, दया और मानव एकता के संदेश से प्रेरणा ले सके।

सदन को संबोधित करते हुए संत सीचेवाल ने कहा कि आज दुनिया भर में मानवता की सेवा के लिए रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं की सराहना की जाती है, लेकिन सिख इतिहास में सदियों पहले ही निःस्वार्थ मानव सेवा की एक अद्वितीय मिसाल कायम हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समय युद्ध के मैदान में भाई घनैया जी बिना किसी भेदभाव के घायल सैनिकों को पानी पिलाते थे। जब इस संबंध में गुरु साहिब ने उन्हें तलब किया तो भाई घनैया जी ने विनम्रता से कहा कि गुरु साहिब ने उन्हें हर इंसान में गुरु का स्वरूप देखने की शिक्षा दी है। इसलिए उन्हें प्रत्येक व्यक्ति में गुरु साहिब का ही रूप दिखाई देता है।

पंजाब में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 के तहत प्रदेश के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची-2026 प्रकाशित कर दी गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 13 अगस्त, 2026 से 12 सितंबर, 2026 तक होगी, जबकि नोटिस चरण तथा दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 13 अगस्त, 2026 से 8 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा।

मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब अनिंदिता मित्रा, आईएएस की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट मतदाता सूची सौंपते हुए एस.आई.आर. प्रक्रिया संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रपत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई। इनमें मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, एन.आर.आई. मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन अथवा स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि 1 अक्टूबर, 2026 को योग्यता तिथि मानते हुए युवा मतदाता नामांकन के लिए पात्र हैं।

हर घर तिरंगा से गूंजेगा राष्ट्रभक्ति का संदेश

तिरंगा हमारी आन-बान-शान : अशोक सरीन हिक्की

जालंधर (जालंधर ब्रीज). हर घर तिरंगा अभियान के तहत जालंधर भाजपा प्रधान अशोक सरीन हिक्की ने सेंट्रल टाऊन स्थित अपने निवास स्थान पर परिवारजनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशभक्ति एवं राष्ट्र गौरव का संदेश दिया।इस अवसर पर मंडल महामंत्री अंकुर रत्ती, मंडल प्रधान मनीष बल, ललित बब्बू, अनुज शारदा, गौरव राय, अर्जुन सिंह हैप्पी, पारस शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी उपस्थित रहे। जिला भाजपा प्रधान अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान आज देशवासियों के भीतर राष्ट्रभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करने वाला जन-अभियान बन चुका है।

तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, वीर जवानों के बलिदान और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा पहुंचे और हर भारतीय के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना और मजबूत हो। इस अभियान के माध्यम से नई पीढ़ी को भी देश के स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक करने का अवसर मिलता है।अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीलंका सीरीज में केएल राहुल निभाएंगे बड़ी भूमिका

गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल की हालिया बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि उनका अनुभव टीम के युवा खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करेगी।

फोटो-बीसीसीआई

स्पोर्ट्स डेस्क. भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल का मानना है कि केएल राहुल आगामी श्रीलंका सीरीज में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शनिवार से शुरू हो रही है। कोच ने कहा है कि टीम को उनका अनुभव और युवा खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करने की उनकी क्षमता काम आएगी। भारतीय टीम शनिवार से गॉल में पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। भारत ने इससे पहले 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था, जिसका हिस्सा केएल राहुल थे।

गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल की हालिया बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि उनका अनुभव टीम के युवा खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करेगी। मोर्कल ने कहा, 'केएल (राहुल), पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बल्लेबाजी में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं, वह वाकई शानदार रहा है। और यही हम उम्मीद करते हैं कि वह युवाओं को यहां की परिस्थितियों से क्या उम्मीद रखी जाए, इस बारे में बातचीत करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में व्यक्तिगत रूप से अपने खेल के बारे में बहुत कुछ सीखा है और यही एक वजह है कि हम यहां 10 दिन पहले आ गए हैं, ताकि खिलाड़ियों को तैयारी का सबसे अच्छा मौका मिल सके। वे यह समझ सकें कि उन्हें यहां की पिच पर रन कैसे बनाने हैं।'

गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने संकेत दिया कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट में भारत बाएं हाथ के तीन स्पिनरों को उतार सकता है क्योंकि कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में अलग-अलग तरह की विविधता और विकेट लेने की क्षमता है। कुलदीप अपनी बाएं हाथ की कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं, जडेजा की सटीक गेंदबाजी बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर सकती है जबकि सुथार पारंपरिक शैली की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की याद दिलाते हैं। मोर्कल ने मीडिया से कहा कि कुलदीप हमारे साथ हैं और वह आक्रामक गेंदबाज हैं। उनका अनुभव और स्तर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये सभी अपनी-अपनी तरह से अलग हैं।' उन्होंने कहा, 'एक (सुथार) गेंद को थोड़ा ज्यादा टर्न कराता है, एक (जडेजा) थोड़ा अधिक सटीक है और मुझे नहीं लगता कि तीन बाएं हाथ के स्पिनरों का होना हमारे लिए कोई बड़ी चिंता है।

आप सरकार लगातार दोषी साबित हो रही : वड़िंग

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार अपनी नाकाबिलियत, अनियमिताओं और भ्रष्टाचार के चलते लगातार दोषी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार न सिर्फ पेपर लीक के लिए आरोपी है, बल्कि उसने अलग-अलग नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा कर युवाओं का भरोसा भी तोड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 21 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजरों और 44 कलस्टर कोऑर्डिनेटरों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए, कहा कि यह सब भर्ती प्रक्रिया के दौरान पाई गैर गंभीर अनियमिताओं के बाद हुआ है। उन्होंने खुलासा किया की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई थी और फरवरी में नतीजा ऐलान दिया गया था, लेकिन कुछ आवेदकों द्वारा इंटरव्यू के दौरान नंबर देते वक्त अनियमिताएं बरते जाने का शक जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा मामले में भर्ती का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया था और रिकार्डों की जांच हेतु वकीलों व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की शमूलियत वाली एक कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा पड़ताल के दौरान नंबर देते समय अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद अदालत ने कमेटी की पड़ताल के आधार पर अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उन्होंने जोर देते हुए, कहा कि इस खुलासे के बाद कोई शक नहीं रह जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया संदेहपूर्ण थी और आवदेकों के शक सही थे।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, J7 NEAR BUS STAND SUBHANPUR (HAMIRA), KAPURTHALA, PUNJAB - 144808, and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.